दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़,मंगलवार 11 फरवरी 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 134

महत्वपूर्ण एवं खास

नक्सलियों ने 3 वाहनों को किया आग के हवाले

रांची (आरएनएस)। झारखंड के लातेहार जिले में सोमवार को संदिग्ध नक्सलियों ने तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार, हथियार लिए हुए पांच लोग लातेहार जिले में चंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के अंतर्गत टोरी कोल सीडिंग के पास पहुंच गए। अपराधियों ने पहले हवा में फायरिंग की और वहां स्थित तीन वाहनों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि वसूली नहीं दिए जाने की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। टोरी रेलवे सीडिंग में, अपराधी और नक्सली प्रायः क्षेत्र का दौरा कर वाहनों को आग लगाते रहते हैं।

आप ने लगाया केन्द्र पर अर्थव्यवस्था डुबोने का आरोप

नईदिल्ली (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अर्थव्यवस्था डुबोने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के मंत्री विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। भारद्वाज ने एक खबर के जवाब में यह ट्वीट किया। खबर के अनुसार, एक व्यक्ति ने रविवार को अपने दो बच्चों की हत्या कर खुद हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा, आगे बहुत खतरनाक समय है, अर्थव्यवस्था डूबने के कारण पूरे परिवारों की हत्या के कई मामले सामने आ सकते हैं। लोगों की नौकरी जा रही है, व्यापार में मंदी है, निवेशक भाग रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री राज्य विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 11 फरवरी को होगी।

यौन प्रताड़ना मामले में गार्गी कॉलेज का दौरा करेगा महिला आयोग

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय की गार्गी कॉलेज की छात्राओं के साथ यौन प्रताड़ना के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है और आयोग जल्दी ही घटना स्थल का दौरा करेगा। आयोग के सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। आयोग का एक दल जल्दी ही स्थिति का जायजा लेने गार्गी कॉलेज जाएगा। खबरों के अनुसार कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान कॉलेज के प्रांगण में बाहरी लोग घुस गये और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में कुछ छात्राओं ने यौन हमले का आरोप लगाया है।

उमर की हिरासत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत का मामला सोमवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। अब्दुल्ला की बहन सारह अब्दुल्ला ने याचिका दायर की है। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया। सिब्बल ने मामले की सुनवाई का अनुरोध किया जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया। उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त, 2019 से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में थे। इस कानून के तहत, उमर अब्दुल्ला की छह महीने की एहतियातन हिरासत अवधि गुरुवार यानी पांच फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर से पी एस ए के तहत हिरासत में ले लिया है।

वर्धा में अग्निदग्ध व्याख्याता ने अस्पताल में दम तोड़ा

नागपुर (आरएनएस)। एक सिरफिरे शख्स द्वारा सार्वजनिक रूप से जलाई गई 24 वर्षीय वर्धा की एक लेक्चरर ने सोमवार को ठीक एक सप्ताह बाद दम तोड़ दिया। पिछले सोमवार को एक एकतरफा प्यार करने वाले शख्स ने महिला लेक्चरर को आग के हवाले कर दिया था।

नोटबंदी तथा जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करना सरकार की बड़ी भूलःचिदंबरम

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और सरकार को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कदम उठाने के साथ-साथ खपत तथा निवेश बढ़ाने के उपाय करने चाहिए।

कांग्रेस के पी. चिदंबरम ने सदन में वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट पर चर्चा की शुरु करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में हैं और सरकार के 'डाक्टर' इसे इससे उबार नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था को 'आईसीयू' में बता रहे है लेकिन सरकार इसे 'आईसीयू' के बाहर 'कुर्सी' पर बिठाकर इलाज करना चाह रही है। सही आर्थिक प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करना चाहिए और खपत तथा निवेश बढ़ाने के उपाय करने चाहिए।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए जनता के हाथ में पैसा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी तथा वस्तु एवं सेवा कर को जल्दबाजी में लागू करना सरकार की भयानक भूल है जिसका असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। इसी का असर है कि आर्थिक वृद्धि दर में लगातार छह तिमाही से गिरावट हो रही है। इतने लंबे समय तक अर्थव्यवस्था का गिरावट में होना पहली बार है।

भारत छोड़ पाकिस्तान भाग रहा आतंकी मूसा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले की जांच में भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आतंकी मुनाफ हलारी मूसा को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मुनाफ हलारी को गुजरात एंटी टेरेरिज्म स्क्वॉड ने गिरफ्तार किया है। वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुनाफ हलारी 1993 में जावेरी बाज़ार में ब्लास्ट मामले में आरोपी था। जांच एजेंसियों को लंबे समय से इसकी तलाश थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुनाफ हलारी महाराष्ट्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के लिए इसने तीन स्कूटर दिए थे।

बम ब्लास्ट से 4 मकान क्षतिग्रस्त, 6 लोग घायल

पटना (आरएनएस)। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के कदमकुआं ते सालिमपुर अहरा के पास बम ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि बम फटने से 6 लोग घायल हो गए है। फिलहाल सभी को आनन-फानन में इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।

जानकारी के मुताबिक, राजधानी पटना के गांधी मैदान से सटे सालिमपुर अहरा के रोड नंबर एक स्थित एक मकान में सोमवार की सुबह करीब आठ बजे विस्फोट हो गया। तेज आवाज के साथ विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के चार मकान क्षतिग्रस्त हो गये। बताया जाता है कि विस्फोट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गये हैं।

घायलों में से एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। बम धमाके के कारण जहां कमरे की दीवार गिर गई वहीं रूम में लगा दरवाजा भी टूट गया। पुलिस ने इसे बम ब्लास्ट बताया है साथ ही एफएसएल की टीम आने के बाद ही कुछ विस्तार से बताने की बात कह रही है। धमाका होते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री

» लोकतांत्रिक भारत में जाति और राजनीति' पर देंगे व्याख्यान

» फरवरी से अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 11 फरवरी से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनफ्रांसिस्को, बोस्टन और न्यूयॉर्क में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 15 से 16 फरवरी को हार्वर्ड में आयोजित 'इंडिया कॉन्फ्रेंस' के विशेष चर्चा में भी हिस्सा लेंगे, जहां 'लोकतांत्रिक भारत में जाति और राजनीति' विषय पर व्याख्यान देंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने 10 दिवसीय अमेरिका प्रवास पर नई दिल्ली से 11 फरवरी को रवाना होंगे।

इस दौरान श्री बघेल हार्वर्ड में आयोजित 'इंडिया कॉन्फ्रेंस' में शामिल होने के साथ ही उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। 'इंडिया कॉन्फ्रेंस' में श्री बघेल के साथ चर्चा विद्वान और कार्यकर्ता सूरज येंगडे द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों से भी मुलाक़ात करेंगे।

चौधरी ने लोकसभा में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुद्दा उठाया

नईदिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में सोमवार को उस वक्त हंगामा शुरू हो गया, जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण से संबंधित फैसले पर सरकार से जवाब मांगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए नौकरियों और प्रोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं हो सकता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया, जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिड़ला और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि मामले को शून्यकाल के दौरान उठाया जाएगा।

मामले को उठाते हुए, चौधरी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर दलितों के सशक्तिकरण के लिए मुहैया कराए गए एक महत्वपूर्ण उपकरण को एक बड़ी क्षति पहुंचाने के लिए उकसाने का काम करने का आरोप लगाया और सरकार से मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा।

लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता को प्रश्नकाल के दौरान मामले को उठाने से रोका और कहा, आपको सदन की कार्यवाही को इस तरह से बाधित नहीं करना चाहिए। आप शून्यकाल में इस मामले को उठा सकते हैं। सरकार आपके सवाल का जवाब देगी। जब कांग्रेस लगातार सरकार से जवाब देने की मांग करती रही, राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप किया और कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सामाजिक कल्याण मंत्री आपके सवाल का शून्यकाल में जवाब देंगे।

शाहीन बाग पर केंद्र व दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

» 17 फरवरी को होगी सुनवाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने राजधानी के शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन को खत्म करने को लेकर तत्काल कोई दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ताओं- वकील अमित साहनी एवं भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग के वकीलों ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ को प्रदर्शन से जनता को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए कोई आदेश या दिशा-निर्देश देने का न्यायालय से आग्रह किया, जिस पर खंडपीठ ने कहा कि वह फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं कर रही। एक सप्ताह और इंतजार कर लें। न्यायालय ने कहा कि वह पहले प्रतिवादियों का पक्ष जानना चाहता है इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया जाता है।

इस बीच प्रदर्शनकारियों की ओर से एक वकील ने प्रदर्शन जारी जारी रखने के अधिकार का जिक्र किया जिस पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को भी धरना प्रदर्शन करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

फिर भी इस बात का खयाल रखा जाना चाहिए कि धरना प्रदर्शन से आम जनता को किसी तरह की कोई समस्या न हो। धरना प्रदर्शन एक निर्धारित क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है तथा इस बीच केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके उन्हें उस दिन तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच भेज सकती है हाईकोर्टः सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान भी पीठ सुनवाई के लिए अहम सवाल या मुद्दा तय कर उसे सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को भेज सकती है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में यह व्यवस्था दी है। न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान भी विभिन्न कानूनी बिंदुओं और प्रश्नों को बड़ी पीठ को भेजने का आदेश दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मामले में गुरुवार (छह फरवरी) को इस बिन्दु पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ क़ानूनी सवालों को वृहद पीठ के सुपुर्द कर सकती है या नहीं। संविधान पीठ ने वृहद पीठ के विचार के लिए सात बिन्दु भी तय किए।

आरक्षण को खत्म करना चाहती है केन्द्र सरकार : राहुल

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण को लेकर जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आरक्षण को खत्म करना चाहती है लेकिन कांग्रेस उसके सपने को पूरा नहीं होने देगी।

गांधी ने संसद भवन परिसर में सोमवार को कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) लगातार संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिले आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वर्ग के हितों की रक्षा करेगी और उनको मिले आरक्षण को खत्म नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों की आज़ादी को खत्म कर रही है। संसद में किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। खुद उनको संसद में बोलने से रोक कर उनके एक चुने हुए प्रतिनिधि के हक को छीना गया है।राहुल ने कहा कि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चुभता है और वह किसी भी तरह से आरक्षण मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सरकार ने कहा है कि आरक्षण किसी का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकुल रोहतगी तथा पी नरसिम्हन ने सरकार की तरफ से कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।

सस्ती बिजली अब राष्ट्रीय राजनीति में बहस का मुद्दा बनाःकेजरीवाल

नईदिल्ली (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को खुशी जाहिर की कि सस्ती बिजली राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने दिखाया है कि इससे वोट भी मिलते हैं।

दिल्ली की आप सरकार की तरह महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी देने संबंधी एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में 24 घंटे सस्ती बिजली हरहाल में उपलब्ध होनी चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे खुशी है कि सस्ती बिजली राष्ट्रीय राजनीति में बहस का मुद्दा बन चुका है।

दिल्ली ने दिखा दिया कि निशुल्क या सस्ती बिजली उपलब्ध कराना संभव है। दिल्ली ने दिखा दिया कि इससे वोट भी मिल सकते हैं। 21वीं सदी के भारत में 24 घंटे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। दिल्ली में आठ फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 11 फरवरी को होगी।

आरक्षण को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस, द्रविड मुन्नेत्र कषगम-द्रमुक, बहुजन समाज पार्टी सहित प्रमुख विपक्षी दलों के सदस्यों ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर लोकसभा में हंगामा किया

और आरोप लगाया कि जिस तरह से इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में जो तर्क दिये गए हैं उससे साफ है कि सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से इन वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकारी नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण मूलभूत अधिकारों में शामिल नहीं है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार की तरफ से यह तर्क आरक्षण को लेकर न्यायालय में दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हजारों साल से दबे कुचले इन वर्गों के लोगों को सरकार को संरक्षण देना चाहिए लेकिन भाजपा सरकार इसके विरोध में न्यायालय में गलत तर्क दे रही है।

कांग्रेस नेता के यह मामला उठाने के साथ ही लगभग सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मामले को उठाया और कहा कि सरकार के आरक्षण समाप्त करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसी बीच कांग्रेस सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का मामला है और सरकार पर आरक्षण खत्म करने का विपक्षी दलों के सदस्यों का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने सदन को बताया कि यह मामला 2012 का है और तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी।